

EXAM GENIUS
Presents
GENIUS
CURRENT
AFFAIRS

In Bilingual
04 & 05 Jan 2026



India's No. 1 Platform for UPSC
| SSC | BANK | RAILWAY Exam

Achieve Success with Exam Genius - Your Ultimate Guide to Reasoning Mastery !



Ques: How many lenders are live on RBI's Unified Lending Interface (ULI) platform as of December 12, 2025?

12 दिसंबर 2025 तक RBI के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म पर कितने ऋणदाता लाइव हैं?

- A) 52
- B) 58
- C) 60
- D) 64
- E) 70

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- As of December 12, 2025, a total of 64 lenders are onboard the Reserve Bank of India's Unified Lending Interface (ULI) platform.
- 12 दिसंबर 2025 तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (ULI) प्लेटफॉर्म पर कुल 64 ऋणदाता शामिल हो चुके हैं।
- These include 41 banks and 23 Non-Banking Financial Companies (NBFCs).
- इनमें 41 बैंक और 23 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) शामिल हैं।
- Lenders are utilising more than 136 data services through ULI across 12 different types of loan journeys.
- ULI के माध्यम से 12 प्रकार की ऋण प्रक्रियाओं में 136 से अधिक डेटा सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है।
- The data services cover authentication and verification, land records from 8 States, satellite data, property search, dairy insights, transliteration, and credit guarantee services.
- डेटा सेवाओं में प्रमाणीकरण व सत्यापन, 8 राज्यों के भूमि रिकॉर्ड, सैटेलाइट डेटा, संपत्ति खोज, डेयरी इनसाइट्स, ट्रांसलिटिरेशन और क्रेडिट गारंटी सेवाएं शामिल हैं।
- ULI operates on a standardised, protocol-driven, open API-based plug-and-play architecture, eliminating complex one-to-one integrations between lenders and data providers.
- ULI एक मानकीकृत, प्रोटोकॉल-आधारित, ओपन API आधारित प्लग-एंड-प्ले संरचना पर कार्य करता है, जिससे ऋणदाताओं और डेटा प्रदाताओं के बीच जटिल वन-टू-वन इंटीग्रेशन की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।



Ques: Rediff.com India Limited has received final approval from which organisation to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP) for its digital payments platform 'RediffPay'?

रेडिफ.कॉम इंडिया लिमिटेड को 'रेडिफपे' डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म के लिए थर्ड-पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में संचालन की अंतिम मंजूरी किस संस्था से मिली है?

- A) Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिज़र्व बैंक
- B) Ministry of Electronics & IT (MeitY) / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय
- C) National Payments Corporation of India (NPCI) / नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया
- D) Securities and Exchange Board of India (SEBI) / भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
- E) Department of Financial Services (DFS) / वित्तीय सेवा विभाग

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Rediff.com India Limited, a subsidiary of Infibeam Avenues Limited, received final approval from the National Payments Corporation of India (NPCI) to operate as a Third-Party Application Provider (TPAP).
- इन्फिबीम एवेन्यूज़ लिमिटेड की सहायक कंपनी रेडिफ.कॉम इंडिया लिमिटेड को TPAP के रूप में कार्य करने के लिए NPCI से अंतिम मंजूरी प्राप्त हुई।
- Following the approval, the company initiated Closed User Group (CUG) testing of its digital payments platform 'RediffPay'.
- मंजूरी के बाद कंपनी ने अपने डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म 'रेडिफपे' का क्लोज़्ड यूज़र ग्रुप (CUG) परीक्षण शुरू किया।
- This testing phase is being conducted ahead of the public launch of RediffPay on the Unified Payments Interface (UPI).
- यह परीक्षण चरण UPI पर रेडिफपे के सार्वजनिक लॉन्च से पहले किया जा रहा है।





Recent News Headlines Related to RBI

- According to the RBI's Report on Trend and Progress of Banking in India, the number of Urban Co-operative Banks (UCBs) declined by 15 during FY25, bringing the total down to 1,457.
- RBI की ट्रेड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार FY25 के दौरान शहरी सहकारी बैंकों की संख्या 15 घटकर 1,457 रह गई।
- According to the RBI report, deposits in India's payments banks increased by 57% year-on-year to ₹25,605 crore as of March 2025.
- आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2025 तक भारत के पेमेंट्स बैंकों की जमा राशि साल-दर-साल 57% बढ़कर ₹25,605 करोड़ हो गई।
- As per the RBI's Report on Trend and Progress of Banking in India 2024–25, the banking system's balance sheet expanded by 11.2% during the year.
- RBI की बैंकिंग में रुझान और प्रगति रिपोर्ट 2024–25 के अनुसार, वर्ष 2024–25 में बैंकिंग प्रणाली का बैलेंस शीट 11.2% बढ़ा।
- According to the RBI report, the total number of ATMs in India declined to 2,51,057 as of March 31, 2025, from 2,53,417 a year earlier.
- RBI रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2025 तक भारत में ATM की कुल संख्या घटकर 2,51,057 रह गई, जो एक वर्ष पहले 2,53,417 थी।
- Aryaman Finance (India) Limited (AFIL) has received a Certificate of Registration (CoR) from the Reserve Bank of India (RBI) to start the business of a Non-Banking Financial Company (NBFC).
- आर्यमन फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (AFIL) को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) के रूप में व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र (CoR) प्राप्त हुआ है।
- The Reserve Bank of India has postponed the implementation of Phase-II of Continuous Clearing and Settlement on Realisation (CCSR) under the Cheque Truncation System, which was earlier scheduled for 3 January 2026, until further notice.
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेक ट्रंकेशन सिस्टम के तहत निरंतर क्लियरिंग एवं सेटलमेंट (CCSR) के फेज-II के क्रियान्वयन को, जो पहले 3 जनवरी 2026 के लिए निर्धारित था, अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।





Ques: Which insurance company was penalised ₹1 crore by IRDAI for serious lapses related to claims settlement, policyholder protection, and corporate governance?

दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के लिए IRDAI ने किस बीमा कंपनी पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया?

- A) Star Health and Allied Insurance / स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस
- B) Care Health Insurance / केयर हेल्थ इंश्योरेंस
- C) HDFC ERGO Health Insurance / एचडीएफसी एर्गो हेल्थ इंश्योरेंस
- D) Niva Bupa Health Insurance / निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस
- E) ICICI Lombard Health Insurance / आईसीआईसीआई लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस

Answer: Option B

Explanation | व्याख्या:

- The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a penalty of ₹1 crore on Care Health Insurance following a remote inspection.
- बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने रिमोट निरीक्षण के बाद केयर हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।
- The penalty was levied due to serious lapses in claims settlement, policyholder protection, and corporate governance standards.
- यह दंड दावों के निपटान, पॉलिसीधारक संरक्षण और कॉरपोरेट गवर्नेंस में गंभीर खामियों के कारण लगाया गया।
- The charges included failure in grievance redressal, cybersecurity lapses, lack of transparency in claims settlement, reinsurance accounting irregularities, and improper handling of unidentified proposal deposits.
- आरोपों में शिकायत निवारण में विफलता, साइबर सुरक्षा में चूक, दावों के निपटान में पारदर्शिता की कमी, पुनर्बीमा लेखांकन में अनियमितताएँ तथा अज्ञात प्रस्ताव जमा राशि के अनुचित प्रबंधन शामिल थे।





Ques: As per RBI data, what was the total value of bank frauds reported in the first half of FY26 (H1FY26)?

RBI के अनुसार FY26 की पहली छमाही (H1FY26) में बैंकों द्वारा रिपोर्ट की गई धोखाधड़ी की कुल राशि कितनी थी?

- A) ₹16,569 crore
- B) ₹18,336 crore
- C) ₹21,515 crore
- D) ₹25,000 crore
- E) ₹17,501 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- According to RBI data, banks reported 5,092 fraud cases amounting to ₹21,515 crore during the first half of FY26 (H1FY26).
- RBI के आँकड़ों के अनुसार FY26 की पहली छमाही (H1FY26) में बैंकों ने 5,092 मामलों में ₹21,515 करोड़ की धोखाधड़ी की सूचना दी।
- The largest share of fraud value was related to advances (loans), accounting for ₹17,501 crore across 4,255 cases.
- धोखाधड़ी की सबसे बड़ी राशि ऋण/एडवांस से जुड़ी रही, जिसमें 4,255 मामलों में ₹17,501 करोड़ शामिल थे।
- Other areas of fraud included deposits, foreign exchange transactions, and card/internet-based frauds.
- धोखाधड़ी के अन्य प्रमुख क्षेत्र जमा, विदेशी मुद्रा लेनदेन और कार्ड/इंटरनेट आधारित धोखाधड़ी रहे।
- Compared to H1FY25, when frauds worth ₹16,569 crore were reported, the amount increased while the number of cases declined in FY26.
- H1FY25 में ₹16,569 करोड़ की धोखाधड़ी रिपोर्ट की गई थी, यानी FY26 में राशि बढ़ी लेकिन मामलों की संख्या घटी।
- RBI clarified that the rise in value was mainly due to reclassification and re-reporting of earlier fraud cases.
- RBI के अनुसार राशि में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पुराने मामलों का पुनर्वर्गीकरण और पुनः रिपोर्टिंग है।
- To tackle digital frauds, the AI-driven MuleHunter.ai platform has been implemented in 23 banks as of 17 December 2025 to identify mule accounts.
- डिजिटल धोखाधड़ी पर रोक लगाने के लिए AI आधारित MuleHunter.ai प्लेटफॉर्म को 17 दिसंबर 2025 तक 23 बैंकों में लागू किया गया है, जो म्यूल खातों की पहचान में मदद करता है।





Ques: 'Gaj', the premium metal credit card, has been launched by which bank and is available exclusively for which category of customers?

'गज' प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है और यह विशेष रूप से किस वर्ग के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है?

- A) HDFC Bank – Mass Retail Customers / एचडीएफसी बैंक – सामान्य ग्राहक
- B) Axis Bank – Corporate Clients / एक्सिस बैंक – कॉर्पोरेट ग्राहक
- C) ICICI Bank – Premium Salary Account Holders / आईसीआईसीआई बैंक – प्रीमियम सैलरी खाताधारक
- D) IDFC First Bank – High-Net-Worth Individuals (HNIs) / आईडीएफसी फर्स्ट बैंक – उच्च-निवल-मूल्य व्यक्ति (HNIs)
- E) SBI – Wealth Management Clients / एसबीआई – वेल्थ मैनेजमेंट ग्राहक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- 'Gaj' is a premium metal credit card launched by IDFC First Bank Limited on an invitation-only basis.
- 'गज' एक प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड है, जिसे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड ने केवल आमंत्रण (इनविटेशन-ओनली) के आधार पर लॉन्च किया है।
- The card is available exclusively for High-Net-Worth Individuals (HNIs).
- यह कार्ड विशेष रूप से उच्च-निवल-मूल्य व्यक्तियों (HNIs) के लिए उपलब्ध है।
- The joining fee for the 'Gaj' credit card is ₹12,500 plus applicable GST.
- 'गज' क्रेडिट कार्ड की जॉइनिंग फीस ₹12,500 + लागू जीएसटी है।
- 'Gaj' represents the top tier of IDFC First Bank's premium metal credit card series known as the Ashva–Mayura–Gaj trilogy.
- 'गज' आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की प्रीमियम मेटल कार्ड श्रृंखला 'अश्व–मयूर–गज' ट्रिलॉजी का शीर्ष स्तर (टॉप टियर) है।

About IDFC First Bank :

- Established : 2015
- HQ : Mumbai
- MD & CEO : V Vaidyanathan
- Tagline : Always You First





Ques: How much does the Government of India plan to borrow through short-term Treasury Bills (T-Bills) over 12 weeks in Q4 of the current financial year?

भारत सरकार चालू वित्त वर्ष की Q4 में 12 सप्ताह के दौरान अल्पकालिक ट्रेजरी बिल (T-Bills) के माध्यम से कितनी राशि उधार लेने की योजना बना रही है?

- A) ₹2.47 lakh crore
- B) ₹3.94 lakh crore
- C) ₹3.50 lakh crore
- D) ₹4.10 lakh crore
- E) ₹3.84 lakh crore

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The Government of India plans to borrow ₹3.84 lakh crore through short-term Treasury Bills over 12 weeks in Q4 to meet short-term funding requirements.
- भारत सरकार अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए Q4 में 12 सप्ताह के दौरान ₹3.84 लाख करोड़ के ट्रेजरी बिल जारी करेगी।
- Weekly T-Bill auctions will be in the range of ₹29,000 crore to ₹35,000 crore, as per the Finance Ministry.
- वित्त मंत्रालय के अनुसार साप्ताहिक T-Bill नीलामी ₹29,000 करोड़ से ₹35,000 करोड़ के बीच होगी।
- The planned Q4 borrowing is ₹10,000 crore lower than the ₹3.94 lakh crore raised in Q4 of the previous financial year.
- यह उधारी पिछले वित्त वर्ष की Q4 में जुटाए गए ₹3.94 लाख करोड़ से ₹10,000 करोड़ कम है।
- Earlier, the government had announced a Q3 T-Bill auction calendar of ₹2.47 lakh crore, ending on 31 December 2025.
- इससे पहले सरकार ने 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने वाली Q3 T-Bill नीलामी योजना ₹2.47 लाख करोड़ की घोषित की थी।





Ques: Who published the Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition), which provides a consolidated and comparable statistical database for Indian States and Union Territories?

भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय डाटाबेस प्रदान करने वाली Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण) किसके द्वारा प्रकाशित की गई है?

- A) Ministry of Statistics and Programme Implementation / सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
B) NITI Aayog / नीति आयोग
C) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
D) Reserve Bank of India / भारतीय रिज़र्व बैंक
E) National Statistical Office / राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10th Edition) has been published by the Reserve Bank of India (RBI).
- Handbook of Statistics on Indian States 2024–25 (10वां संस्करण) भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा प्रकाशित की गई है।
- The handbook serves as a consolidated and comparable statistical resource for Indian States and Union Territories, with time-series data available from 1951 onwards.
- यह पुस्तिका भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक समेकित एवं तुलनात्मक सांख्यिकीय संसाधन है, जिसमें 1951 से समय-श्रृंखला डेटा उपलब्ध है।
- It is prepared by the Regional Economy Monitoring Division (REMD) under the Department of Economic and Policy Research (DEPR), using inputs from RBI regional offices and multiple data sources.
- इसे आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (DEPR) के अंतर्गत क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था निगरानी प्रभाग (REMD) द्वारा RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न डेटा स्रोतों के आधार पर तैयार किया गया है।
- The 10th edition introduces a new External Sector section and adds 11 new state-wise statistical tables, enhancing analysis of regional trends and disparities.
- 10वें संस्करण में एक नया बाह्य क्षेत्र (External Sector) अनुभाग जोड़ा गया है तथा 11 नए राज्य-वार सांख्यिकीय तालिकाएँ शामिल की गई हैं, जिससे क्षेत्रीय प्रवृत्तियों और असमानताओं का विश्लेषण बेहतर होता है।





Ques: According to the Reserve Bank of India (RBI), which digital payment system accounted for the largest share in transaction volume during FY 2024–25?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के अनुसार वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान लेन-देन की संख्या के आधार पर किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रही?

- A) RTGS / आरटीजीएस
- B) NEFT / एनईएफटी
- C) IMPS / आईएमपीएस
- D) UPI / यूपीआई
- E) Cheques / चेक

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- According to the RBI report, the share of small-value retail digital payments is increasing rapidly in India.
- RBI रिपोर्ट के अनुसार भारत में छोटे मूल्य के खुदरा डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी तेज़ी से बढ़ रही है।
- During FY 2024–25, digital payments recorded a growth of 17.9 percent in value terms.
- वित्त वर्ष 2024–25 में डिजिटल भुगतानों में मूल्य के आधार पर 17.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
- Digital payments accounted for 97.6 percent of India's total payments in value terms, highlighting their dominance in the payment ecosystem.
- मूल्य के आधार पर भारत के कुल भुगतानों में डिजिटल भुगतानों की हिस्सेदारी 97.6 प्रतिशत रही, जो इनके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
- In volume terms, digital payments witnessed a much higher growth of 35 percent during the year.
- लेन-देन की संख्या के आधार पर डिजिटल भुगतानों में 35 प्रतिशत की तेज़ वृद्धि देखी गई।
- This surge in transaction volumes was mainly driven by the increasing use of digital modes for small-value transactions.
- यह वृद्धि मुख्य रूप से छोटे मूल्य के लेन-देन में डिजिटल माध्यमों के बढ़ते उपयोग के कारण हुई।
- UPI emerged as the digital payment system with the largest share in transaction volume, reflecting its widespread adoption for everyday payments.
- UPI लेन-देन की संख्या के आधार पर सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान माध्यम बनकर उभरा, जो दैनिक भुगतानों में इसके व्यापक उपयोग को दर्शाता है।
- In contrast, RTGS accounted for the largest share in value terms, as it is primarily used for high-value transactions.





Ques: Under the Regional Connectivity Scheme – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik), how many routes have been operationalised across India as of 30 November?

क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (UDAN) के अंतर्गत 30 नवंबर तक पूरे भारत में कितने मार्ग (Routes) परिचालित किए जा चुके हैं?

- A) 512
- B) 589
- C) 651
- D) 702
- E) 725

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Regional Connectivity Scheme – UDAN (Ude Desh ka Aam Nagrik) is a flagship initiative of the Government of India aimed at improving regional air connectivity and making air travel affordable.
- क्षेत्रीय संपर्क योजना – उड़ान (UDAN) भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढ़ाना और हवाई यात्रा को किफायती बनाना है।
- As of 30 November, a total of 651 routes have been operationalised under the UDAN scheme.
- 30 नवंबर तक, UDAN योजना के अंतर्गत कुल 651 मार्ग संचालित किए जा चुके हैं।
- The scheme has connected 93 unserved and underserved airports, along with 15 heliports and 2 water aerodromes.
- इस योजना के तहत 93 गैर-सेवित और अल्प-सेवित हवाई अड्डों, 15 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रोम को जोड़ा गया है।
- Around 157 lakh passengers have benefited, and about 3.27 lakh UDAN flights have been operated so far.
- अब तक लगभग 157 लाख यात्रियों को लाभ मिला है और 3.27 लाख उड़ान उड़ानें संचालित की जा चुकी हैं।
- In Uttar Pradesh, UDAN covers 87 routes connecting 12 airports, reflecting strong regional penetration.
- उत्तर प्रदेश में UDAN के तहत 87 मार्गों के माध्यम से 12 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है।
- The scheme was launched on 21 October 2016 for a 10-year period and is implemented by the Ministry of Civil Aviation.
- यह योजना 21 अक्टूबर 2016 को 10 वर्षों की अवधि के लिए शुरू की गई थी और इसे नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है।





Ques: Which state has become the first in India to host the Indian Artificial Intelligence Research Organization (IAIRO), approved to be set up at GIFT City?

भारत का पहला कौन-सा राज्य है जहाँ GIFT City में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन (IAIRO) की स्थापना को मंजूरी दी गई है?

- A) Maharashtra / महाराष्ट्र
- B) Karnataka / कर्नाटक
- C) Telangana / तेलंगाना
- D) Gujarat / गुजरात
- E) Tamil Nadu / तमिलनाडु

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Gujarat Government, led by Chief Minister Bhupendra Patel, granted in-principle approval for setting up the Indian Artificial Intelligence Research Organization (IAIRO) at GIFT City, Gandhinagar.
- मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाली गुजरात सरकार ने गांधीनगर स्थित GIFT City में भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन (IAIRO) की स्थापना को सैद्धांतिक मंजूरी दी।
- With this initiative, Gujarat has become the first state in India to host a dedicated AI research organization.
- इस पहल के साथ गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ एक विशेष AI अनुसंधान संस्था स्थापित की जा रही है।
- The IAIRO is scheduled to become operational from 1 January 2026.
- IAIRO का संचालन 1 जनवरी 2026 से शुरू होने की योजना है।
- The organization will be set up as a non-profit Special Purpose Vehicle (SPV) under Section 8 of the Companies Act, 2013.
- यह संगठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अंतर्गत एक गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- IAIRO will be established through a tripartite partnership involving the Gujarat Government, Government of India, and the Indian Pharmaceutical Alliance (IPA).
- IAIRO की स्थापना गुजरात सरकार, भारत सरकार और इंडियन फार्मास्यूटिकल एलायंस (IPA) के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से की जाएगी।
- The total five-year budget of ₹300 crore will be shared equally (33.33% each) among the three partners, with the IPA contributing ₹25 crore in 2025–26.



Ques: Where was the maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR-120) successfully conducted?

पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR-120) का प्रथम उड़ान परीक्षण कहाँ सफलतापूर्वक किया गया?

- A) Integrated Test Range, Chandipur / इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, चांदीपुर
- B) Pokhran Test Range / पोखरण परीक्षण क्षेत्र
- C) Abdul Kalam Island / अब्दुल कलाम द्वीप
- D) Mahendragiri Test Facility / महेंद्रगिरि परीक्षण केंद्र
- E) Balasore Firing Range / बालासोर फायरिंग रेंज

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- The maiden flight test of the Pinaka Long Range Guided Rocket (LRGR-120) was successfully conducted at the Integrated Test Range (ITR), Chandipur.
- पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट (LRGR-120) का प्रथम उड़ान परीक्षण इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR), चांदीपुर में सफलतापूर्वक किया गया।
- During the test, the rocket was validated for its maximum strike range of 120 kilometres.
- इस परीक्षण के दौरान रॉकेट की अधिकतम 120 किलोमीटर की मारक क्षमता का सफल सत्यापन किया गया।
- The LRGR-120 has been designed by the Armament Research and Development Establishment (ARDE) in collaboration with the High Energy Materials Research Laboratory (HEMRL), with support from the Defence Research and Development Laboratory (DRDL) and Research Centre Imarat (RCI).
- LRGR-120 को आर्मेन्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट (ARDE) ने हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लैबोरेटरी (HEMRL) के सहयोग से विकसित किया है, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी (DRDL) और रिसर्च सेंटर इमारत (RCI) का भी समर्थन रहा है।
- The Pinaka Rocket System is named after "Pinaka", the celestial bow of Lord Shiva.
- पिनाका रॉकेट सिस्टम का नाम भगवान शिव के दिव्य धनुष 'पिनाका' से लिया गया है।
- The development of the Pinaka system began in the late 1980s by DRDO as an indigenous alternative to the Russian BM-21 'Grad' rocket system.
- पिनाका प्रणाली का विकास DRDO द्वारा 1980 के दशक के उत्तरार्ध में रूसी BM-21 'ग्रेड' प्रणाली के स्वदेशी विकल्प के रूप में शुरू किया गया था।
- The Pinaka Rocket System earned legendary status during the 1999 Kargil War for effectively neutralising enemy positions located on high-altitude mountain tops.
- 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान ऊँचाई पर स्थित दुश्मन ठिकानों को नष्ट करने में प्रभावी भूमिका निभाने के कारण पिनाका रॉकेट सिस्टम को विशेष पहचान मिली।





Ques: Which major telecom policy document was released by the Department of Telecommunications (DoT) to manage and allocate radio-frequency spectrum in India with effect from 30 December 2025?

30 दिसंबर 2025 से प्रभावी भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा कौन-सा प्रमुख नीति दस्तावेज जारी किया गया?

- A) National Digital Communications Policy 2024 / राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2024
- B) Indian Telegraph Spectrum Policy / भारतीय टेलीग्राफ स्पेक्ट्रम नीति
- C) National Broadband Mission Plan / राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन योजना
- D) National Frequency Allocation Plan 2025 / राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025
- E) Spectrum Harmonisation Framework / स्पेक्ट्रम समन्वय ढांचा

Answer: Option D

Explanation | व्याख्या:

- The Department of Telecommunications (DoT), under the Ministry of Communications, released the National Frequency Allocation Plan 2025 (NFAP-2025) for the management and allocation of radio-frequency spectrum in India.
- संचार मंत्रालय के अंतर्गत दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारत में रेडियो-फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के प्रबंधन और आवंटन हेतु राष्ट्रीय आवृत्ति आवंटन योजना 2025 (NFAP-2025) जारी की।
- NFAP-2025 formally came into effect on 30 December 2025 and serves as a key reference for spectrum managers, wireless service providers, and telecom equipment manufacturers.
- NFAP-2025 औपचारिक रूप से 30 दिसंबर 2025 से लागू हुई और यह स्पेक्ट्रम प्रबंधकों, वायरलेस ऑपरेटर्स और दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ दस्तावेज है।
- The plan supports the expansion of 5G, 6G, satellite services, and future communication needs, in alignment with global standards.
- यह योजना वैश्विक मानकों के अनुरूप 5G, 6G, उपग्रह सेवाओं और भविष्य की संचार आवश्यकताओं के विस्तार को समर्थन देती है।
- NFAP-2025 allocates spectrum for radio communication services across a wide frequency range from 8.3 kHz to 3000 GHz.
- NFAP-2025 के अंतर्गत 8.3 किलोहर्ट्ज़ से 3000 गीगाहर्ट्ज़ तक की आवृत्ति सीमा में विभिन्न रेडियो संचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया गया है।
- Key improvements include identification of the 6,425–7,125 MHz band for International Mobile Telecommunications (IMT) and allocation of Ka, Q, and V bands for high-throughput satellite-based services.





Recent Penalties imposed on Banks:

- **The Reserve Bank of India (RBI) imposed regulatory restrictions on two Urban Cooperative Banks—The Gauhati Cooperative Urban Bank Limited in Assam and The Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank Limited in Gujarat.**
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने दो शहरी सहकारी बैंकों—असम स्थित गौहाटी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड और गुजरात स्थित वलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड—पर नियामकीय प्रतिबंध लगाए हैं।
- **The Reserve Bank of India imposed a monetary penalty of ₹99.30 lakh on Jammu and Kashmir Bank Limited.**
 - भारतीय रिज़र्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड पर ₹99.30 लाख का मौद्रिक जुर्माना लगाया है।
- **RBI imposed a penalty of ₹91 lakh on HDFC Bank for violations related to the Banking Regulation Act and deficiencies in statutory and regulatory compliance, including KYC-related lapses.**
 - RBI ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम और सांविधिक एवं नियामक अनुपालन में कमियों, विशेषकर KYC से संबंधित त्रुटियों के लिए HDFC बैंक पर ₹91 लाख का जुर्माना लगाया।
- **Reserve Bank of India (RBI) imposed a penalty of ₹39.60 lakh on Tamilnad Mercantile Bank Limited.**
 - भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड पर 39.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
- **The Central Consumer Protection Authority (CCPA) imposed a penalty of ₹8,00,000 each on Dikshant IAS and Abhimanu IAS for misleading advertisements, unfair trade practices, and violation of consumer rights under the Consumer Protection Act, 2019.**
 - केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने Dikshant IAS और Abhimanu IAS पर भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के लिए प्रत्येक पर 8,00,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
- **The Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) imposed a ₹1 crore penalty on Liberty General Insurance for violations related to outsourcing, commission payments, and remuneration to intermediaries.**
 - भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर आउटसोर्सिंग, कमीशन भुगतान और मध्यस्थों को पारिश्रमिक देने से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया।





Ques: Who inaugurated and flagged off the inaugural flight of the indigenous next-generation civil helicopter Dhruv-NG in Bengaluru?

बेंगलुरु में स्वदेशी अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव-NG की उद्घाटन उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई?

- A) Rajnath Singh / राजनाथ सिंह
- B) Jyotiraditya Scindia / ज्योतिरादित्य सिंधिया
- C) Ram Mohan Naidu / राम मोहन नायडू
- D) Nitin Gadkari / नितिन गडकरी
- E) Ashwini Vaishnaw / अश्विनी वैष्णव

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- Union Minister for Civil Aviation, Ram Mohan Naidu, inaugurated and flagged off the inaugural flight of the indigenous next-generation civil helicopter Dhruv-NG at Hindustan Aeronautics Limited (HAL) facilities in Bengaluru, Karnataka.
- केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) परिसर में स्वदेशी अगली पीढ़ी के नागरिक हेलीकॉप्टर ध्रुव-NG की पहली उड़ान का उद्घाटन एवं शुभारंभ किया।
- Dhruv-NG has been developed by HAL as an Advanced Light Helicopter (ALH), designed as a light twin-engine, multi-role civil helicopter in the 5.5-tonne class.
- ध्रुव-NG को HAL द्वारा उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (ALH) के रूप में विकसित किया गया है, जो 5.5 टन श्रेणी का हल्का, ट्विन-इंजन, बहुउद्देश्यीय नागरिक हेलीकॉप्टर है।
- It is powered by twin Shakti 1H1C engines and can carry up to 14 passengers, with a maximum speed of 285 km/h and a range of 630 km.
- इसमें ट्विन शक्ति 1H1C इंजन लगे हैं, यह अधिकतम 14 यात्रियों को ले जा सकता है, जिसकी अधिकतम गति 285 किमी/घंटा और रेंज 630 किमी है।
- The helicopter features a civil-certified glass cockpit, a service ceiling of 6,000 metres, and a payload capacity of up to 1,000 kg, strengthening India's indigenous civil aviation capabilities.
- यह हेलीकॉप्टर सिविल-प्रमाणित ग्लास कॉकपिट, 6,000 मीटर की सेवा ऊँचाई और 1,000 किलोग्राम तक की पेलोड क्षमता के साथ भारत की स्वदेशी नागरिक उड्डयन क्षमताओं को सशक्त बनाता है।

About Hindustan Aeronautics Limited :

- Established : 1964
- HQ : Bengaluru, Karnataka
- CMD : Dr. D.K. Sunil





Ques : INSV Kaundinya, recently in news, is based on which historical source?

हाल ही में समाचारों में रहा INSV कौंडिन्य किस ऐतिहासिक स्रोत पर आधारित है?

- A) Ajanta cave paintings / अजंता गुफा चित्रकारी
- B) Konark temple carvings / कोणार्क मंदिर की नक्काशी
- C) Harappan dockyard remains / हड़प्पाकालीन बंदरगाह के अवशेष
- D) Indus Valley seals / सिंधु घाटी की मुहरें
- E) Sun temple manuscripts / सूर्य मंदिर की पांडुलिपियाँ

Answer: Option A

Explanation :

- INSV Kaundinya is an engineless, indigenously built stitched sailing vessel of the Indian Navy.
- INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना का बिना इंजन वाला, स्वदेशी सिला-जुड़ा नौकायन पोत है।
- The vessel sailed on its maiden overseas voyage from Porbandar (Gujarat) to Muscat (Oman).
- यह पोत पोरबंदर (गुजरात) से मस्कट (ओमान) की अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्रा पर रवाना हुआ।
- The journey covers about 1,400 km and is expected to take around 15 days, using wind and oars for propulsion.
- यह यात्रा लगभग 1,400 किमी की है और हवा व चप्पुओं के सहारे करीब 15 दिन में पूरी होने की उम्मीद है।
- The expedition aims to revive and showcase India's ancient maritime heritage and historic sea routes linking India with Oman.
- इस अभियान का उद्देश्य भारत की प्राचीन समुद्री विरासत और भारत-ओमान के ऐतिहासिक समुद्री मार्गों को पुनर्जीवित व प्रदर्शित करना है।
- The vessel is based on a 5th-century CE ship depicted in Ajanta cave paintings.
- यह पोत अजंता गुफाओं में दर्शाए गए 5वीं शताब्दी ईस्वी के जहाज़ पर आधारित है।
- INSV Kaundinya was launched in February 2025 at Goa.
- INSV कौंडिन्य को फरवरी 2025 में गोवा में लॉन्च किया गया।
- It was built using ancient stitched-shipbuilding techniques by traditional artisans under master shipwright Babu Sankaran.
- इसे प्राचीन सिले-जुड़े जहाज़ निर्माण तकनीक से मास्टर शिपराइट बाबू शंकरन के मार्गदर्शन में पारंपरिक कारीगरों ने बनाया।
- The project was undertaken under a tripartite MoU between the Ministry of Culture, Indian Navy and M/s Hodi Innovations.





Ques: Which ministry is responsible for implementing Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 4.0, under which more than 53 lakh candidates were trained in the last five years?

पिछले पाँच वर्षों में 53 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने वाली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है?

- A) Ministry of Skill Development and Entrepreneurship / कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
- B) Ministry of Education / शिक्षा मंत्रालय
- C) Ministry of Labour and Employment / श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
- D) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
- E) Ministry of Youth Affairs and Sports / युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana (PMKVY) 4.0 is implemented by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship.
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 का कार्यान्वयन कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- Over the last five years, more than 53 lakh candidates have been trained under PMKVY.
- पिछले पाँच वर्षों में, PMKVY के अंतर्गत 53 लाख से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।
- Around 70.5% of surveyed candidates were placed in their desired skill sectors, indicating strong placement outcomes.
- सर्वेक्षण किए गए उम्मीदवारों में से लगभग 70.5% को उनकी इच्छित कौशल क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ।
- PMKVY is a flagship skill development scheme of the Government of India, launched in 2015, and implemented by the National Skill Development Corporation (NSDC).
- PMKVY भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल विकास योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा लागू किया गया।
- The scheme focuses on short-term training, certification, and placement, aiming to upskill and reskill Indian youth for industry-relevant employment, including school dropouts.
- यह योजना अल्पकालिक प्रशिक्षण, प्रमाणन और प्लेसमेंट पर केंद्रित है तथा स्कूल छोड़ चुके युवाओं सहित भारतीय युवाओं को उद्योग-उपयुक्त कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।
- Eligibility criteria include: age 14–35 years, Indian nationality, no minimum educational qualification, preference to unemployed/underemployed youth, and mandatory Aadhaar card.





Recent Facilities Launched in Banking & Insurance Sector:

- **NPCI launched upihelp.npci.org.in as a centralized platform to improve transparency and user control over UPI AutoPay standing instructions, reduce dark patterns, and enable easy portability of mandates.**
 - एनपीसीआई ने यूपीआई ऑटोपे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस पर पारदर्शिता और उपयोगकर्ता नियंत्रण में सुधार करने, डार्क पैटर्न को कम करने और मैडेट की आसान पोर्टेबिलिटी को सक्षम करने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में upihelp.npci.org.in लॉन्च किया है।
- **Galaxy Health Insurance, promoted by V Jagannathan and TVS Group's Venu Srinivasan, has launched a new health insurance product named "Galaxy Twin 360".**
 - वी. जगन्नाथन और टीवीएस ग्रुप के वेणु श्रीनिवासन द्वारा प्रवर्तित गैलेक्सी हेल्थ इंश्योरेंस ने "Galaxy Twin 360" नामक नया स्वास्थ्य बीमा उत्पाद लॉन्च किया है।
- **Canara ai1Pe has been launched by Canara Bank. It allows users to link savings or current accounts from any bank to make and receive UPI payments.**
 - Canara ai1Pe को केनरा बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यह उपयोगकर्ताओं को किसी भी बैंक के बचत या चालू खाते को लिंक करके UPI भुगतान करने और प्राप्त करने की सुविधा देता है।
- **Axis Bank Limited, a leading private sector lender in India, launched a new digital loan product called 'Digital Merchant Cash Advance Loans' for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs).**
 - भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक लिमिटेड ने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) के लिए 'Digital Merchant Cash Advance Loans' नामक नया डिजिटल लोन उत्पाद लॉन्च किया।
- **The IndusInd Bank Jio-bp Mobility+ Credit Card was launched on 10 December 2025.**
 - इंडसइंड बैंक जियो-बीपी मोबिलिटी+ क्रेडिट कार्ड 10 दिसंबर 2025 को लॉन्च किया गया।
- **South Indian Bank has launched the RuPay SIB Paytag, a contactless NFC-enabled payment sticker/device.**
 - साउथ इंडियन बैंक ने संपर्करहित NFC आधारित भुगतान स्टिकर/डिवाइस RuPay SIB Paytag लॉन्च किया है।
- **IDFC First Bank has launched the 'IDFC First Global Savings Account' for Non-Resident Indians (NRIs).**
 - आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अनिवासी भारतीयों (NRI) के लिए 'IDFC First Global Savings Account' लॉन्च किया है।





Ques: What was the theme of the 5th National Conference of Chief Secretaries held in New Delhi?

नई दिल्ली में आयोजित 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन का विषय क्या था?

- A) Cooperative Federalism for New India / नए भारत के लिए सहकारी संघवाद
- B) Governance Reforms and Digital India / शासन सुधार और डिजिटल इंडिया
- C) Human Capital for Viksit Bharat / विकसित भारत के लिए मानव पूंजी
- D) Inclusive Growth and Social Justice / समावेशी विकास और सामाजिक न्याय
- E) Innovation and Sustainable Development / नवाचार और सतत विकास

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The 5th National Conference of Chief Secretaries was held in New Delhi and was chaired by Prime Minister Narendra Modi.
- 5वां राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
- The theme of the conference was “Human Capital for Viksit Bharat”, highlighting the role of human development in achieving the vision of a developed India.
- सम्मेलन का विषय “विकसित भारत के लिए मानव पूंजी” था, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मानव संसाधन के महत्व को दर्शाता है।
- Special emphasis was placed on five key areas: early childhood education, schooling, skilling, higher education, and sports & extracurricular activities.
- इसमें पाँच प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया: प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा तथा खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ।

Genius





Ques: Which bird species' breeding habitats were approved for protection during the 68th Executive Committee meeting of the National Mission for Clean Ganga (NMCG)?

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 68वीं कार्यकारी समिति बैठक में किस पक्षी प्रजाति के प्रजनन स्थलों के संरक्षण को मंजूरी दी गई?

- A) Sarus Crane / सारस क्रेन
- B) Great Indian Bustard / ग्रेट इंडियन बस्टर्ड
- C) Lesser Flamingo / लेसर फ्लेमिंगो
- D) Black-necked Stork / ब्लैक-नेक्ड स्टॉक
- E) Indian Skimmer / इंडियन स्किमर

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- The 68th Executive Committee meeting of the National Mission for Clean Ganga (NMCG) was chaired by Director General Shri Rajeev Kumar Mittal and focused on ensuring Aviral (uninterrupted) and Nirmal (unpolluted) flow of the Ganga and its tributaries.
- राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) की 68वीं कार्यकारी समिति बैठक की अध्यक्षता महानिदेशक श्री राजीव कुमार मिश्र ने की, जिसमें गंगा और उसकी सहायक नदियों की अविरल और निर्मल धारा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
- The committee approved a pioneering project for the protection of breeding habitats of sandbar-nesting birds, specifically the Indian Skimmer.
- समिति ने रेत के टापुओं पर घोंसला बनाने वाले पक्षियों, विशेष रूप से इंडियन स्किमर, के प्रजनन स्थलों के संरक्षण हेतु एक अग्रणी परियोजना को मंजूरी दी।
- Nest monitoring of the Indian Skimmer will continue in the Chambal and Lower Ganga regions and will be expanded to Bijnor, Narora, and Prayagraj.
- इंडियन स्किमर के घोंसलों की निगरानी चंबल और निचली गंगा क्षेत्रों में जारी रहेगी तथा बिजनौर, नरौरा और प्रयागराज तक इसका विस्तार किया जाएगा।
- This initiative completes NMCG's holistic faunal biodiversity framework by adding avifauna conservation to existing programmes for dolphins, turtles, and muggers.
- यह पहल NMCG के समग्र जीव-जंतु जैव-विविधता संरक्षण ढांचे को पूर्ण करती है, जिसमें डॉल्फिन, कछुए और मगरमच्छ (मगर) के साथ अब पक्षियों को भी शामिल किया गया है।
- Local communities will be trained to minimise human disturbance on sandbars and support awareness and conservation activities.





- स्थानीय समुदायों को रेत के टापुओं पर मानवीय हस्तक्षेप कम करने और जागरूकता व संरक्षण गतिविधियों में सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा।
- Under Nature-Based Solutions (NbS), in-situ treatment of drains at Shastri Park, Gaushala, and Kailash Nagar/Ramesh Nagar in Delhi was approved to rejuvenate the Yamuna.
- नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस (NbS) के तहत दिल्ली में शास्त्री पार्क, गौशाला और कैलाश नगर/रमेश नगर नालों के लिए यमुना के पुनर्जीवन हेतु इन-सीटू उपचार को मंजूरी दी गई।
- Raw sewage will be treated on-site using eco-friendly methods such as rock filters, stone masonry, and aquatic plants before entering the Yamuna.
- यमुना में प्रवेश से पहले कच्चे सीवेज का उपचार रॉक फ़िल्टर, पत्थर की चिनाई और जलीय पौधों जैसी पर्यावरण-अनुकूल तकनीकों से किया जाएगा।
- Revised infrastructure approvals were granted for projects in Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, and West Bengal to maintain project momentum.
- परियोजनाओं की गति बनाए रखने हेतु उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में विभिन्न अवसंरचना परियोजनाओं को संशोधित स्वीकृति दी गई।
- A master plan was approved to restore the sanctity of the Gomti River's origin at Pilibhit in Uttar Pradesh.
- उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में गोमती नदी के उद्गम स्थल की पवित्रता बहाल करने के लिए एक मास्टर प्लान को भी मंजूरी दी गई।

About National Mission for Clean Ganga :

- Launched in : 2011 under the Societies Registration Act 1860
- Flagship Program : Namami Gange (launched in June 2014)
- Parent Ministry : Ministry of Jal Shakti
- implemented by : National Council for Rejuvenation, Protection and Management of River Ganga





Ques : Who is the author of the political memoir “107 Days”?

“107 डेज़” नामक राजनीतिक आत्मकथा की लेखिका कौन हैं?

- A) Hillary Clinton / हिलेरी क्लिंटन
- B) Michelle Obama / मिशेल ओबामा
- C) Kamala Harris / कमला हैरिस
- D) Nikki Haley / निक्की हेली
- E) Condoleezza Rice / कॉंडोलीज़ा राइस

Answer: Option C

Explanation :

- “107 Days” is a political memoir written by Kamala Harris.
- “107 डेज़” कमला हैरिस द्वारा लिखी गई एक राजनीतिक आत्मकथा है।
- The book reflects on the 107-day presidential campaign journey and key political experiences.
- यह पुस्तक 107 दिनों के राष्ट्रपति चुनाव अभियान और महत्वपूर्ण राजनीतिक अनुभवों पर आधारित है।
- Kamala Harris is an American politician and attorney.
- कमला हैरिस एक अमेरिकी राजनीतिज्ञ और वकील हैं।
- She served as the 49th Vice President of the United States from 2021 to 2025.
- उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति के रूप में 2021 से 2025 तक कार्य किया।
- She served under President Joe Biden.
- उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडन के अधीन कार्य किया।
- Kamala Harris is the first woman, first African-American, and first Asian-American Vice President of the United States.
- कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला, पहली अफ्रीकी-अमेरिकी और पहली एशियाई-अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं।





Ques Who has been appointed as the Interim Director General (DG) of the National Investigation Agency (NIA)?

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अंतरिम महानिदेशक (DG) के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A) Sadanand Vasant Date / सदानंद वसंत दाते
- B) Rakesh Asthana / राकेश अस्थाना
- C) Ajit Doval / अजीत डोभाल
- D) Alok Verma / आलोक वर्मा
- E) Rakesh Agarwal / राकेश अग्रवाल

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Rakesh Agarwal, who is currently serving as the Special Director General of the National Investigation Agency (NIA), has been appointed as the Interim Director General (DG) of the NIA.
- राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में वर्तमान में विशेष महानिदेशक के पद पर कार्यरत राकेश अग्रवाल को NIA का अंतरिम महानिदेशक (DG) नियुक्त किया गया है।
- He will hold the additional charge of Director General until a regular DG is appointed or until further orders are issued.
- वह नियमित महानिदेशक की नियुक्ति होने या आगे के आदेश जारी होने तक यह अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
- Rakesh Agarwal has replaced Sadanand Vasant Date in the position of Director General of NIA.
- राकेश अग्रवाल ने इस पद पर सदानंद वसंत दाते का स्थान लिया है।
- NIA, established in 2008, in New Delhi (Delhi), following the 26/11 Mumbai attack in Mumbai, Maharashtra. It is a premier counter-terrorism agency, which investigates terrorism, terror financing, and organized crime affecting national security.
- एनआईए की स्थापना 2008 में नई दिल्ली (दिल्ली) में 26/11 के हमले के बाद हुई थी। यह महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था। यह एक प्रमुख आतंकवाद-विरोधी एजेंसी है, जो आतंकवाद, आतंकवाद वित्तपोषण और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले संगठित अपराध की जांच करती है।





Recent News Headlines Related to Schemes

- **ASPIRE stands for A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry, and Entrepreneurship and is implemented by the Ministry of MSME.**
- ASPIRE का पूर्ण रूप A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry, and Entrepreneurship है और इसे MSME मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है।
- **Delhi Chief Minister Rekha Gupta launched the “Atal Canteen Scheme” to provide nutritious and hygienic meals at a highly subsidised rate of ₹5 per plate.**
- दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने केवल ₹5 प्रति थाली में पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए “अटल कैंटीन योजना” शुरू की।
- **The Union Home Ministry revised the guidelines under the ‘Support to Poor Prisoners’ scheme, which was launched in 2023.**
- केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2023 में शुरू की गई ‘सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर्स’ योजना के तहत दिशानिर्देशों में संशोधन किया है।
- **The Supreme Court ruled that families of doctors who died while performing COVID-19 duties are entitled to ₹50 lakh insurance under the Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana (PMGKY).**
- सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर डॉक्टरों के परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत ₹50 लाख का बीमा मिलेगा।
- **The Government has approved Namo Drone Didi as a Central Sector Scheme with an outlay of ₹1,261 crore for 2023–24 to 2025–26.**
- सरकार ने नमो ड्रोन दीदी को 2023–24 से 2025–26 के लिए ₹1,261 करोड़ के परिव्यय के साथ केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में मंजूरी दी है।
- **PM E-DRIVE scheme was notified on 29 September 2024 with a total allocation of ₹4,391 crore.**
- PM E-DRIVE योजना 29 सितंबर 2024 को ₹4,391 करोड़ के कुल आवंटन के साथ अधिसूचित की गई।
- **System for Pension Administration – Raksha (SPARSH) has onboarded over 31 lakh defence pensioners across India and Nepal as of November 2025. SPARSH is a flagship Digital India initiative of the Ministry of Defence**





Ques: Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDUNASS) has entered into a strategic partnership with which institution to strengthen ethical governance in EPFO?

पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक््योरिटी (PDUNASS) ने EPFO में नैतिक शासन को मजबूत करने के लिए किस संस्था के साथ रणनीतिक साझेदारी की है?

- A) IC Centre for Governance (ICCFG) / आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस
- B) Indian Institute of Public Administration (IIPA) / भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
- C) Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) / लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी
- D) National Institute of Financial Management (NIFM) / राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान
- E) Centre for Good Governance (CGG) / सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Pandit Deendayal Upadhyaya National Academy of Social Security (PDUNASS), the apex training institution of the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), has entered into a strategic partnership with the IC Centre for Governance (ICCFG).
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की शीर्ष प्रशिक्षण संस्था पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल एकेडमी ऑफ सोशल सिक््योरिटी (PDUNASS) ने आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस (ICCFG) के साथ रणनीतिक साझेदारी की है।
- This initiative complements the operational reforms introduced by EPFO in 2025, including the simplified withdrawal framework and the centralized pension payment system.
- यह पहल 2025 में EPFO द्वारा शुरू किए गए परिचालन सुधारों—जैसे सरलीकृत निकासी ढांचा और केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली—को पूरक बनाती है।
- As EPFO increasingly reduces manual processes through automation, the partnership emphasizes the need for higher standards of moral judgment in complex and discretionary cases.
- EPFO में स्वचालन के माध्यम से मैनुअल प्रक्रियाएँ कम होने के साथ-साथ जटिल और विवेकाधीन मामलों में उच्च नैतिक निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया गया है।





- The PDUNASS–ICCFG collaboration aims to ensure that the human element of governance keeps pace with the growing digital systems.
- PDUNASS–ICCFG सहयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शासन का मानवीय पक्ष डिजिटल प्रणालियों के साथ समान गति से आगे बढ़े।
- PDUNASS is the premier learning and research institute of EPFO under the Ministry of Labour & Employment, Government of India, and plays a key role in capacity building aligned with Labour Codes and Digital India initiatives.
- PDUNASS, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत EPFO की प्रमुख प्रशिक्षण एवं शोध संस्था है, जो श्रम संहिताओं और डिजिटल इंडिया जैसी राष्ट्रीय पहलों के अनुरूप क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
- The IC Centre for Governance (ICCFG) is a reputed non-profit institution dedicated to strengthening ethical governance through executive education and policy dialogue for senior civil servants and PSU leaders.
- आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस (ICCFG) एक प्रतिष्ठित गैर-लाभकारी संस्था है, जो वरिष्ठ सिविल सेवकों और PSU नेतृत्व के लिए कार्यकारी शिक्षा और नीति संवाद के माध्यम से नैतिक शासन को सुदृढ़ करती है।
- ICCfG's "Ethics in Public Governance" modules are widely recognised for their practical relevance and transformative impact on public administration.
- ICCfG के "एथिक्स इन पब्लिक गवर्नेंस" मॉड्यूल अपनी व्यावहारिक उपयोगिता और सार्वजनिक प्रशासन में परिवर्तनकारी प्रभाव के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध हैं।

EXAM
Genius





Recent News Headlines related to Defence

- **India successfully test-fired the K-4, an intermediate-range Submarine-Launched Ballistic Missile (SLBM), from INS Arighaat, India's second nuclear-powered submarine, in the Bay of Bengal off the coast of Visakhapatnam, Andhra Pradesh.**
• भारत ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट के पास बंगाल की खाड़ी में भारत की दूसरी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी INS अरिघात से के-4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
- **Samudra Pratap (Yard 1267) is India's first indigenously designed and built Pollution Control Vessel (PCV), formally inducted by the Indian Coast Guard at Goa Shipyard Limited (GSL).**
• समुद्र प्रताप (यार्ड 1267) भारत की पहली स्वदेशी डिज़ाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत (PCV) है, जिसे भारतीय तट रक्षक ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) में औपचारिक रूप से शामिल किया।
- **Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched the BlueBird Block-2 communication satellite into Low Earth Orbit (LEO) using the Launch Vehicle Mark-3 (LVM3-M6) on a dedicated commercial mission.**
• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने ब्लूबर्ड ब्लॉक-2 संचार उपग्रह को लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) में LVM3-M6 रॉकेट के माध्यम से एक समर्पित वाणिज्यिक मिशन के तहत सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
- **Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) Limited delivered INS Anjadip, the third of eight Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft (ASW SWC), to the Indian Navy at Chennai Port Trust, Tamil Nadu.**
• गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) लिमिटेड ने INS अंजादीप, जो आठ पनडुब्बी रोधी उथले जलपोत (ASW SWC) में तीसरा है, को चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट, तमिलनाडु में भारतीय नौसेना को सौंपा।
- **NASA reported a loss of communication with the MAVEN spacecraft while it was orbiting Mars.**
• नासा ने मंगल की कक्षा में स्थित MAVEN अंतरिक्षयान से संपर्क टूटने की सूचना दी।
- **The Indian Navy commissioned INAS 335 'Ospreys', its second squadron of MH-60R (Romeo) multi-role naval helicopters, at INS Hansa, Goa.**
• भारतीय नौसेना ने गोवा स्थित INS हंसा में MH-60R (रोमियो) बहु-भूमिका नौसैनिक हेलीकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन INAS 335 'Ospreys' को कमीशन किया।





Ques: What is the total value of defence contracts signed by the Ministry of Defence for the procurement of CQB Carbines and Heavy Weight Torpedoes?
रक्षा मंत्रालय द्वारा CQB कार्बाइन और हेवी वेट टॉरपीडो की खरीद के लिए किए गए रक्षा अनुबंधों का कुल मूल्य कितना है?

- A) ₹3,500 crore
- B) ₹4,200 crore
- C) ₹4,666 crore
- D) ₹5,100 crore
- E) ₹6,000 crore

Answer: Option C

Explanation | व्याख्या:

- The Ministry of Defence signed defence contracts worth ₹4,666 crore in New Delhi to strengthen India's military capabilities.
- रक्षा मंत्रालय ने भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में ₹4,666 करोड़ के रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
- A contract worth ₹2,770 crore was signed with Bharat Forge Limited and PLR Systems Private Limited.
- ₹2,770 करोड़ का एक अनुबंध भारत फोर्ज लिमिटेड और PLR सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया।
- This contract is for the procurement of over 4 lakh Close Quarter Battle (CQB) Carbines.
- यह अनुबंध 4 लाख से अधिक क्लोज क्वार्टर बैटल (CQB) कार्बाइन की खरीद के लिए है।
- The CQB Carbines will be inducted into the Indian Army and Indian Navy, replacing outdated legacy weapons.
- CQB कार्बाइन भारतीय सेना और भारतीय नौसेना को प्रदान की जाएंगी, जिससे पुराने हथियारों को बदला जाएगा।
- Another contract worth ₹1,896 crore was signed with WASS Submarine Systems S.R.L. of Italy.
- ₹1,896 करोड़ का एक अन्य अनुबंध इटली की WASS Submarine Systems S.R.L. के साथ किया गया।





Ques: Who became the highest wicket-taker in Women's T20 International cricket by claiming her 152nd wicket?

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 152वां विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनीं?

- A) Deepti Sharma / दीप्ति शर्मा
- B) Ellyse Perry / एलिस पेरी
- C) Jhulan Goswami / झूलन गोस्वामी
- D) Megan Schutt / मेगन शुट
- E) Anisa Mohammed / अनिसा मोहम्मद

Answer: Option A

Explanation | व्याख्या:

- Indian women's cricket achieved a major milestone as Deepti Sharma became the highest wicket-taker in Women's T20 International cricket.
- भारतीय महिला क्रिकेट ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की जब दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज बनीं।
- Deepti Sharma achieved this landmark during the 5th T20I match against Sri Lanka at Thiruvananthapuram.
- दीप्ति शर्मा ने यह उपलब्धि तिरुवनंतपुरम में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए 5वें टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में हासिल की।
- She claimed her 152nd T20I wicket, surpassing Australia's Megan Schutt, who earlier held the record with 151 wickets.
- उन्होंने अपना 152वां टी20 अंतरराष्ट्रीय विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया की मेगन शुट (151 विकेट) का रिकॉर्ड तोड़ा।
- With this achievement, Deepti Sharma now stands alone at the top of the all-time wicket-takers list in Women's T20Is.
- इस उपलब्धि के साथ दीप्ति शर्मा महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वकालिक सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं।





Recent News Headlines Related to Summits / conference

- **The Department of Science and Technology (DST) organised the National Workshop on Strengthening of Geospatial Ecosystem at Yashobhoomi, New Delhi.**
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा यशोभूमि, नई दिल्ली में भू-स्थानिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- **India will officially assume the chair of the Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), a global initiative to remove conflict diamonds from the supply chain, starting January 1, 2026.**
• भारत 1 जनवरी 2026 से किम्बर्ली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम (KPCS), जो वैश्विक सप्लाई चेन से कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स हटाने के लिए एक पहल है, की अध्यक्षता संभालेगा।
- **The 20th Conference of the Parties (CoP20) to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) was held from 24 November to 05 December 2025.**
• वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) का 20वां CoP 24 नवंबर से 05 दिसंबर 2025 तक आयोजित हुआ।
- **The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) partners — India, the United States, Australia, and Japan — conducted their first Field Training Exercise on the sidelines of Operation Christmas Drop.**
• क्वाड समूह के सदस्य देशों — भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान — ने ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप के दौरान अपना पहला फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास आयोजित किया।
- **The 11th Conference of the State Parties (COSP-11) to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) was held in Doha, Qatar.**
• संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक अभिसमय (UNCAC) के तहत राज्यों का 11वां सम्मेलन (COSP-11) दोहा, कतर में आयोजित किया गया।
- **CeRAI – Centre for Responsible AI, IIT Madras, in collaboration with IndiaAI Mission under MeitY, is hosting a Pre-Summit Event on 11 December in Chennai.**
• CeRAI – सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल AI, आईआईटी मद्रास, MeitY के तहत IndiaAI मिशन के सहयोग से 11 दिसंबर को चेन्नई में प्री-सम्मिट कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।





Ques: Who was Bangladesh's first female Prime Minister, who served two terms and was later honoured with the 'Mother of Democracy' award?

बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थीं, जिन्होंने दो कार्यकाल पूरे किए और बाद में 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' सम्मान से सम्मानित हुईं?

- A) Sheikh Hasina / शेख हसीना
- B) Rasheda Choudhury / राशिदा चौधरी
- C) Benazir Bhutto / बेनज़ीर भुट्टो
- D) Khaleda Mashraf / खालिदा मशरफ
- E) Begum Khaleda Zia / बेगम खालिदा जिया

Answer: Option E

Explanation | व्याख्या:

- Former Prime Minister of Bangladesh, Begum Khaleda Zia, chairperson of the Bangladesh Nationalist Party (BNP), passed away at the age of 80 in Dhaka, Bangladesh.
- बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में ढाका में निधन हो गया।
- She served as the Prime Minister of Bangladesh twice — first from 1991 to 1996 and later from 2001 to 2006.
- उन्होंने दो बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया — 1991 से 1996 तक और पुनः 2001 से 2006 तक।
- She joined the Bangladesh Nationalist Party in 1982; the party was founded by Ziaur Rahman.
- उन्होंने 1982 में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी में प्रवेश किया, जिसकी स्थापना जियाउर रहमान ने की थी।
- In 2022, she was honoured with the 'Mother of Democracy' award by the Canadian Human Rights International Organization (CHRIO).
- वर्ष 2022 में उन्हें कैनेडियन ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन (CHRIO) द्वारा 'मदर ऑफ डेमोक्रेसी' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- Begum Khaleda Zia was Bangladesh's first female Prime Minister and the second female Prime Minister in the Muslim world after Benazir Bhutto.
- बेगम खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं और मुस्लिम विश्व में बेनज़ीर भुट्टो के बाद दूसरी महिला प्रधानमंत्री थीं।